



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

पं. 542]
No. 542]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 31, 1989/भाद्र 9, 1911
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 1989/BHADRA 9, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ तात्परा हो जाती हैं जिससे कि यह जल्द संग्रहण के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

अम भवालय

अम जी वी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों)
और प्रकार्जी उपचान्द्र अधिनियम, 1955 के अधीन समाचारपत्र स्थापन
नियोजकों और उनके अम जी वी पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मचारियों
को नोटिस।

नई दिल्ली, 31 अगस्त 1989

का.आ. 684(अ) :—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के अम
भवालय को अधिकृतना सं. का.आ. 527(अ) और का.आ. 528(अ),
जो दोनों तारीखे 17 जुलाई, 1985 को हैं, अम जी वी पत्रकार और
अन्य समाचार पत्र कर्मचारों सेवा की शर्तों और प्रकार्जी उपचान्द्र अधिनियम,
1955 (1955 का 45) को धारा 9 और धारा 13ग के अधीन अम जी वी
पत्रकार गैर-पत्रकार सम च.रपत्र कर्मचारियों को मजूरी-दरे निर्धारित
या तुरंतीक्रिय करने के लिए मत्त्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक देश
निवृत्त न्यायालीय न्यायभूति श्री यू. एस. वडायत की अध्यक्षता में दो
महान् नोडों का गठन किया गया।

और उक्त दोनों ने अपनी सिफारियों कर दी हैं :

और केन्द्रीय सरकार उक्त सिफारियों में कुछ उपाय करते का
प्रस्ताव करती है जो उसके विचार में उक्त सिफारियों के स्वरूप में महत्व-
पूर्ण परिवर्तन करते हैं :—

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपचारा (2) के
खण्ड (क) के परन्तुके ग्रन्तिरण में ऐसे दोनों अधिनियमों को जिनके
निम्नलिखित उपायरणों द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, सूचना दी
जाती है कि वे उस तारीख से जिसको राजपत्र में प्रकाशित इस अधिकृतना
की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि
के नींवित तिथि रूप में निम्नलिखित दो अस्यावेदन भेजें :—

सचिव,

भारत सरकार,

अम भवालय,

अम शक्ति भूमि,

नई दिल्ली।

प्रस्तावित उपायरण :

(i) अम जी वी पत्रकार और गैर अम जी वी पत्रकार
कर्मचारियों के लिए दोनों को सिफारियों के अध्याय 9 के अधीन आग

1 के अनुभाग 5 के अधीन मकान किराया भत्ता के संबंध में, सारणी
3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अधीतः—

सारणी-3

(मकान किराया भत्ता की दर (वेतन का प्रतिशत)

समाचारपत्र स्था- 20 लाख और 10 से 20 लाख 10 लाख से कम
एन की वर्ग उससे अधिक की के बीच की जनसंख्या की जनसंख्या वाले
जनसंख्या वाले वाले नगर/कस्बे नगर/कस्बे
नगर, कस्बे

1	2	3	4
IV	45	30	20
V	40	30	20
VI	40	30	20
VII	40	30	20
VIII	50	30	20
IX	40	30	20

1 जनवरी, 1988 से आगे की अवधि के लिए पहले से दिया गया
मकान किराया भत्ता प्रस्तावित उपांतरणों के अधीन जब वे अंतिम
रूप से प्रधिसूचित कर दिए जाएं, अनुमय मकान किराया भत्ता के मद्दे
समाप्तोजित किया जाएगा।

[सं. एस. 33014/1/89-इस्यू.वी.]

MINISTRY OF LABOUR

NOTICE UNDER WORKING JOURNALISTS
AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES
(CONDITIONS OF SERVICE) AND MISCE-
LLANEOUS PROVISIONS ACT, 1955 TO
NEWSPAPER ESTABLISHMENT EMPLO-
EES AND THEIR WORKING JOURNALISTS
AND NON-JOURNALIST EMPLOYEES.

New Delhi, the 31st August, 1989

S.O. 684 (E):—Whereas the Central Government by the notifications of the Government of India in the Ministry of Labour Nos. S.O. 527(E) and S. O. 528(E), both dated the 17th July, 1985 constituted two wage boards under section 9 and section 13C of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) under the Chairmanship of Justice Shri U. N. Bhachawat, a retired Judge of the Madhya Pradesh High Court for fixing or revising the rates of wages of working journalists and non-journalist newspaper employees;

And whereas, the said Boards have made their recommendations;

And whereas, the Central Government proposes to make certain modifications to the said recommendations, which in its opinion affect important alterations in the character of the said recommendations;

Now therefore, in pursuance of the proviso to clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act notice is hereby given to all persons

टिप्पणी:— अंतर अधीन मकान किराया भत्ते की दर, किसी भी नगर
में समाचारपत्र स्थापन के किसी वर्ग के अधीन कर्मचारियों
के किसी समूह के लिए 1200 रुपए के अधिकतम के
अधीन रहते हुए होगी।

(ii) अध्याय 9 के अधीन भाग 1 के अनुभाग 5 के अधीन नगर
प्रतिकारात्मक भत्ता के संबंध में सारणी IV के स्थान पर निम्नलिखित
सारणी रखी जाएगी, अधीतः—

रु. सारणी-4

नगर प्रतिकारात्मक भत्ता

(वर प्रतिमास)

स्थापन का वर्ग 20 लाख या 10 से 20 लाख 4 लाख या
उससे अधिक के बीच जनसंख्या उससे अधिक
संख्या वाले वाले नगर/कस्बे जनसंख्या वाले
नगर/कस्बे नगर/कस्बे

1	2	3	4
रु.	रु.	रु.	रु.
I	100	75	20
II	75	50	20
III	60	35	20
	50	30	20

likely to be affected by the following modifications to make their representations in writing within a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public to :

The Secretary to the Government of India.
Ministry of Labour,
Shram Shakti Bhavan,
New Delhi.

Proposed modifications :

(i) For Table III, in relation to the House Rent Allowance under section V of Part I under Chapter IX of the recommendations of the Boards for Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees, the following Table shall be substituted namely :—

TABLE III
Rates of House Rent Allowance
(Percentage of Pay)

Class of Newspaper Establishment.	Cities/ Towns with population of 20 lakhs and above.	Cities/ Towns with population between 10 to 20 lakhs	Cities/ Towns with population less than 10 lakhs.
IA	15	14	13
I	14	13	12
II	13	12	11
III	12	11	10
IV	11	10	9
V	10	9	8
VI	9	8	7
VII	8	7	6
VIII	7	6	5
IX	6	5	4

Note :— The rates of House Rent Allowance mentioned above are subject to a maximum of Rs. 1200/- for any group of employees under any class of newspaper establishment in any city.

(ii) For Table IV in relation to City Compensatory Allowance under Section V of Part I under Chapter IX, the following table shall be substituted, namely :—

TABLE IV
CITY COMPENSATORY ALLOWANCE
(Rates per mensum)

Class of Establish- ment	Cities/ Towns with popu- lation of 20 lakhs and above.	Cities/ Towns with popu- lation bet- ween 10 to 20 lakhs.	Cities/ Towns with popu- lation of 4 lakhs or more.
	Rs.	Rs.	Rs.
IA	100	75	20
I	75	50	20
II	60	35	20
III	50	30	20
IV	45	30	20
V	40	30	20
VI	40	30	20
VII	40	30	20
VIII	40	30	20
IX	40	30	20

The House Rent Allowance already paid for the period commencing on the 1st day of January, 1988 onwards shall be adjusted against the House Rent Allowance admissible under the proposed modifications as and when finally notified

[No. S—33014/1/89-W.B.]

अम जीवी पत्रकार और अन्य समाजिक वर्ग कर्मचारी (सेवा की लाई) और प्रकीर्ण उपनिवेश, 1955 के अधीन समाजार-एजेंसी नियोजकों और उनके अम जीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों को तोटिस।

का.पा. 645 (ग) :—लेट्रोप यरकार न भारत सरकार के अम मत्रालय की अधिकारियों का का.पा. 527 (ग) और का.पा. 528 (अ), ज८ दिनों तारीख 17 जूलाई, 1985 की है, अम जीवी पत्रकार और गैर-पत्रकार कर्मचारी (सेवा की लाई) और प्रकीर्ण उपनिवेश, 1955 (1955 का 45) की अन्तरा 9 और धारा 13ग के अधीन अम जीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार एजेंसी कर्मचारियों की मजदूरी-दरों निर्धारित या पुनर्गठित करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक सेवा नियुक्त न्यायाधीश न्यायमूलि श्री मु. एन. बाधावल की अध्यक्षता में दो मजदूरी बोर्डों का गठन किया था।

अम उन बोर्डों ने अपनी विकारियों का नियमी है;

और केन्द्रीय यरकार उनके सिफारियों में कुछ उपातरण करने का प्रस्ताव करती है जो उनके विचार में उनके विकारियों के स्वत्ता में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं :—

अब, अतः उन अधिकारियों की धारा 12 की उपाधारा (2) के बांड (क) के परस्तुक के अनुसरण में ऐसे अपनी अकितयों की जिनके नियम-नियिकन उपातरणों द्वारा प्रभावित होते की संभावना है, सूचना दी जाती है कि वे उम तारीख से जिगकी राजपत्र में प्रकाशित इस अधिकारियों की

प्रतियां जलता को उपलब्ध करा दी जाती है, तो संविधान की प्रविधि के अन्तर निम्निकृत रूप में निम्नलिखित को प्रस्तावित करते हैं:—

सचिव,
मार्ग सरकार,
श्रम विभाग,
श्रम विभाग भवन,
नई विल्हॉम।
प्रस्तावित उपांतरण :

(i) अम जीवी पत्रकार और गैर-श्रम जीवी समाजाधारपत्र कर्मचारियों के लिए बोर्डों की सिफारिशों के प्रधानाय 9 के प्रधोन भाग II के प्रतुभाग 5 के प्रधोन मकान किराया भत्ता के संबंध में, सारणी 3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

सारणी-3

(मकान किराया भत्ता की वर्तेन का प्रतिशत)

समाजाधारपत्र एजेंटी का वर्ग	20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	10 से 20 लाख, 10 लाख से कम वाले नगर/कस्बे	13
I	15	14	13
II	16	14	13

टिप्पणी:— अपर वर्णित मकान किराया भत्ता की वर्तेन कीसी भी नगर में समाजाधारपत्र एजेंटी के किसी वर्ग के प्रधोन कर्मचारियों के किसी समूह के लिए 1200 रुपए के प्रधिकरण के प्रधीन रहते हुए होगी।

(ii) प्रधानाय 9 के प्रधोन भाग II के प्रतुभाग 5 के प्रधोन नगर प्रतिकरात्मक भत्ता के संबंध में सारणी IV के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

सारणी-4

नगर प्रतिकरात्मक भत्ता

(दर प्रतिमास)

स्थान नं. नं. 20 वाला जनसंख्या के बीच जनसंख्या अधिक की जनसंख्या संबंध वाले नगर/कस्बे वाले नगर/कस्बे	10 से 20 लाख 4 लाख वा उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	रु.	रु.	रु.
I		100	75	20
II		75	50	20

1 जनवरी, 1988 से आगे की वर्किंग के लिए पहले से दिया गया मकान किराया भत्ता प्रस्तावित उपांतरणों के प्रधोन जब वे अंतिम

रूप से प्रधिसूचित कर दिए जाएं, अनुज्ञेय मकान किराया भत्ता के मद्दे समापोजित किया जाएगा।

[सं. एम.-33014/1/89-उम्मी. वी.]

पत्रमा बैंकेटाइलम, उप सचिव

NOTICE UNDER WORKING JOURNALISTS AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 1955 TO NEWS AGENCY EMPLOYERS AND THEIR WORKING JOURNALISTS AND NON-JOURNALIST EMPLOYEES.

S.O. 685 (E):—Whereas the Central Government by the notifications of the Government of India in the Ministry of Labour Nos. S. O. 527 (E) and S.O. 528(E) both dated the 17th July, 1985 constituted two wage boards under section 9 and section 13C of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) under the Chairmanship of Justice Shri U. N. Bhachawat, a retired Judge of the Madhya Pradesh High Court for fixing or revising the rates of wages of working journalists and non-journalist news agency employees;

And whereas, the said Boards have made their recommendations;

And whereas, the Central Government proposes to make certain modifications to the said recommendations, which is its opinion affect important alterations in the character of the said recommendations;

Now therefore, in pursuance of the proviso to clause (A) of sub-section (2) of section 12 of the said Act notice is hereby given to all persons likely to be affected by the following modifications to make their representations in writing within a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public to:

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Labour,
Shram Shakti Bhavan,
New Delhi.

Proposed modifications :

(i) For Table III, in relation to the House Rent Allowance under Section V of Part II under Chapter IX of the recommendations of the Boards for Working Journalists and Non-Journalist News-paper Employees, the following Table shall be substituted namely :—

TABLE III

Rates of House Rent Allowance
(Percentage of Pay)

Class of News Agency	Cities/ Towns with population of 20 lakhs and above	Cities/ Towns with population between 10 to 20 lakhs	Cities/ Towns with population of less than 10 lakhs.
I	15	14	13
II	15	14	13

Note :— The rates of House Rent Allowance mentioned above are subject to a maximum of Rs. 1200/- for any group of employees under any class of News Agency in any city.

(ii) For Table IV in relation to City Compensatory Allowance under Section V of Part II under Chapter IX, the following table shall be substituted, namely :—

TABLE IV

Rates of City Compensatory Allowance
(Rates per mensum)

Class of Establishment	Cities/ Towns with population of 20 lakhs and above	Cities/ Towns with population between 10 to 20 lakhs	Cities/ Towns with population of 4 lakhs or more.
	Rs.	Rs.	Rs.
I	100	75	20
II	75	50	20

The House Rent Allowance already paid for the period commencing on the 1st day of January, 1988 onwards shall be adjusted against the House Rent Allowance admissible under the proposed modifications as and when finally notified.

[No. S—33014/1/89-WB.]

PADMA VENKATACHALAM, Dy. Secy.

